

उमरिया जिले के कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 में दो लेन एवं पेक्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु 23.287 हे. वनभूमि एवं 7.136 हे. राजस्व वन भूमि कुल 30.423 हे. भूमि म.प्र. सड़क विकास निगम शहडोल को उपयोग पर देने बावत।

1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की सैद्धान्तिक अनुमति क्रमांक-6-MPC-014/2016-BHO/191 दिनांक 23.12.2016		
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क.एफ - 5/776/2016 / 10-11/2789 दिनांक 24.12.2016		
शर्त क्र	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिसूचित शर्तें	आवेदक संस्था द्वारा शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
1.	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपवर्तित रहेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने के उपरांत भी प्रश्नाधीन वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। वचनपत्र संलग्न है।
2.	उपयोगकर्ता एजेंसी के आधिपत्य में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत ही वन भूमि का आधिपत्य सौंपा जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन के अतिरिक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शासकीय एवं निजी भूमि उपलब्ध/अधिग्रहित की गई है। वचनपत्र संलग्न है।
3.	(अ) वन विभाग के द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 11.570 हे. गैर वनभूमि (खसरा क्रमांक 182/7, 186, 229 ग्राम टोंकड़ा तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा) एवं 19.470 हे. गैर वनभूमि (खसरा क्रमांक 818/1/1, ग्राम रापड़ी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा) कुल	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना की कुल लागत रुपये 2,30,66,683 (रु. दो करोड़ तीस लाख छियासठ हजार छः सौ तिरासी मात्र) का अंतरण भारत सरकार के केम्पा के खाता क्रमांक 037100101025216 कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली-110003 आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉपलेक्स नई दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371 में माध्यम से कर दिया गया है जिसका अर्थोराईजेशन नंबर

-141-

	30.423 है। पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।	P17010688740276 है (छायाप्रति संलग्न है)
	(ब) अतिक्रमणमुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।	अतिक्रमणमुक्त गैर वन भूमि मण्डल अधिकारी शाजापुर (म.प्र.) को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कलेक्टर जिला - आगर-मालवा के आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
	(स) इस गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में द्वितीय स्तर की स्वीकृति के पूरे हस्तांतरित व नामांतरित किया जायेगा।	न्यायालय कलेक्टर जिला आगरमालवा मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण क्र. 33/अ-19(3)/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 14/07/2015 के माध्यम से प्रस्तावित गैर वनभूमि को वनविभाग को हस्तांतरित व नामांतरित किया जा चुका है। खसरा नक्शा संलग्न है।
	(द) इस गैर वनभूमि को राज्य के वनविभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927, के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित किया जायेगा।	वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
	(इ) चयनित गैर वनभूमि को सर्वे ऑफ इंडिया की 1:5000 पैमाने की टोपोग्राफिक पर दर्शाया जायेगा। गैर वनभूमि के प्रत्येक कोने के बियरिंग एवं अंतर के अतिरिक्त जी.पी.एस.रीडिंग (लेटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड) दर्ज किये जायेंगे।	वनविभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
4.	उपयोगकर्ता एजेंसी वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वनीकरण की लागत मय सीमांकन, सर्वेक्षण, स्थायी पिलर स्थापना इत्यादि व्यय वन विभाग को पेशगी जमा करेंगे। क्षतिपूरक वनीकरण का 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वनीकरण योजना में भविष्य में संभावित लागत वृद्धि हेतु प्रावधान रहेगा।	रु. 2,30,66,683 (रु. दो करोड़ तीस लाख छियासठ हजार छ. सौ तिरासी मात्र) का अंतरण भारत सरकार के केम्पा के खाता क्रमांक 037100101025216 कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉर्पोरेट्स नई दिल्ली-110003 आई.एफ.एस.सी कोड CORP00000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉर्पोरेट्स नई दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी कोड CORP00000371 में माध्यम से कर दिया गया है जिसका अर्थोराईजेशन नंबर P17010688740276 है (छायाप्रति संलग्न है) भविष्य में संभावित लागत वृद्धि के भुगतान हेतु वचनपत्र संलग्न है। वचनपत्र संलग्न है।
5.	(अ) समादेश याचिका (सी) क्र. 202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार	प्रभावित 30.423 है। वनभूमि की नेट प्रेजेण्ट वैल्यू रु. 2,26,16,127 दो करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार एक सौ सताईस मात्र। भारत सरकार के केम्पा के खात क्र. 037100101025216 लोधी कॉर्पोरेट्स नई दिल्ली-110003 आई.एफ.एस.सी.कोड CORP00000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉर्पोरेट्स नई

	तथा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-ii) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे संबंधित पत्रांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य शासन, उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 30.423 हे. क्षेत्र की वन भूमि के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।	दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी कोड CORP0000371 एवं खता कं. SB01025216 के माध्यम से कर दिया गया है जिसका अर्थोसर्जेशन नंबर P17010789523488 है (खायाप्राप्ति संलग्न है।)
	(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय राशि है तो यह राशि राज्य शासन द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जायेगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।	कटनी-उमरिया-शाहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने के फलस्वरूप। प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य रु. 2,26,16,127/- (दो करोड़ छब्बीस लाख सोलह हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) भारत सरकार के कम्पा के खाता कं. 037100101025216 कार्पोरेशन बैंक, लोधी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 आई.एफ.एस.सी. कोड CORP0000371 में दिनांक 05.01.2017 को कार्पोरेशन बैंक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेस-1 लोधी रोड़ नई दिल्ली जिसका आई.एफ.एस.सी. कोड नं. CORP0000371 एवं खता कं. SB01025216 के माध्यम से कर दिया गया है जिसका अर्थोसर्जेशन नं. P17010789523488 है। विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय राशि है तो यह राशि उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा राज्य शासन को भुगतान की जायेगी। वचनपत्र संलग्न है।
6.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Madhya Pradesh के कार्पोरेशन बैंक लोधी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली - 110003 में स्थित खाता संख्या CAF SB01025216 में इस्तेमालित की जायेगी।	बिन्दु क्र. 2 के अनुसार पालन किया गया है।

7.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि में अधिकतम 5707 वृक्षों का पालन किया जा सकेगा। परंतु परियोजना के उन्नयन हेतु अत्यन्त आवश्यक एवं न्यूनतम वृक्षों का ही पालन सुनिश्चित किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि में अधिकतम 5707 वृक्षों का पालन किया जा सकेगा। परन्तु परियोजना के उन्नयन हेतु अत्यन्त आवश्यक एवं न्यूनतम वृक्षों का ही पालन सुनिश्चित किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
8.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार लागू होने पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर सकेगे।	लागू नहीं।
9.	भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत समय-समय पर फ्लाई एश के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
10.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस के मानदण्डों के अनुरूप मार्ग के सेन्ट्रल वर्ज / दोनों ओर पट्टी में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा अपने खर्च पर वन विभाग की देख-रेख में सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
11.	मार्ग पर गति सीमा दर्शाने वाले सूचना पटल लगाये जायेंगे।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में मार्ग पर गति सीमा दर्शाने वाले सूचना पटल लगाये जायेंगे। वचनपत्र संलग्न है।

12.	वनभूमि में कोई भी लेबर केम नहीं लगाये जायेंगे।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.सा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्र में किसी भी तरह के लेबर केम की स्थापना नहीं की जावेगी। वचनपत्र संलग्न है।
13.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में जहां तक संभव हो वैधानिक स्रोत से वैकल्पिक ईंधन अथवा वन विभाग / वन विकास निगम से क्रय कर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराई जायेगी।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.सा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में जहां तक संभव हो वैधानिक स्रोत से वैकल्पिक ईंधन अथवा वन विभाग / वन विकास निगम से क्रय कर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराई जावेगी। वचनपत्र संलग्न है।
14.	निर्माण काय में लगे स्टॉफ एवं श्रमिकों द्वारा वनस्थिति जीवों इत्यादित वनसंपदा को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, यह उपयोगकर्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.सा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में निर्माण कार्य में लगे स्टॉफ एवं श्रमिकों द्वारा वनस्थिति एवं जीवों इत्यादि वनसंपदा को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी यह उपयोगकर्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी। वचनपत्र संलग्न है।
15.	वनक्षेत्र के बाहर प्रस्तावित लेबर केम परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही हटाये जायेंगे एवं श्रमिकों को वापस भेजा जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.सा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में वन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित लेबर केम परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही हटाये जायेंगे एवं श्रमिकों को वापस भेजा जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
16.	भारत सरकार के अनुमोदन के बिना व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी दशा में अन्य किसी	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.सा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4

	एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जायेगा।	परियोजना के अंतर्गत उन्मयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यापवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में भारत सरकार के अनुमोदन के बिना व्यापवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी दशा में अन्य किसी एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
17.	परियोजना की लागत पर व्यपवर्तित वन भूमि का सीमांकन कराया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.श.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्मयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यापवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा परियोजना की लागत पर व्यपवर्तित वन भूमि का सीमांकन कराया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
18.	प्रस्ताव का ले-आउट प्लान भारत सरकार के अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.श.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्मयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यापवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में प्रस्ताव का ले-आउट प्लान भारत सरकार के अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
19.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.श.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्मयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यापवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नाधीन वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
20.	वनविभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप मलबे का निपटान किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.श.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्मयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यापवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में वन विभाग द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप मलबे का निपटान किया जायेगा।

		वचनपत्र संलग्न है।
21.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर भू-संरक्षण के उपाय किये जायेंगे।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर भू-संरक्षण के उपाय किये जायेंगे। वचनपत्र संलग्न है।
22.	निर्माण सामग्री परिवहन हेतु वन क्षेत्र में कोई भी नया अथवा अतिरिक्त पथ नहीं बनाया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में निर्माण सामग्री परिवहन हेतु वन क्षेत्र में कोई भी नया अथवा अतिरिक्त पथ नहीं बनाया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
23.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर वन विभाग के परामर्श के अनुसार वन्य जीवों के आवागमन हेतु ओवर / अपडरपास का निर्माण कराया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक होने पर वन विभाग के परामर्श के अनुसार वन्य जीवों के आवागमन हेतु ओवर/अंडरपास का निर्माण कराया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
24.	इस व्यपवर्तन स्वीकृति की अवधि उपयोगकर्ता अभिकरण को प्रदत्त तीज अवधि अथवा परियोजना का जीवनकाल समाप्त होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जायेगी।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण ह अभिवचन करते हैं कि इस व्यपवर्तन स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जायेगी। वचनपत्र संलग्न है।

25.	उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को राज्य के नोडल अधिकारी को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को राज्य के नोडल अधिकारी को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
26.	राज्य शासन द्वारा वन भूमि के व्यपवर्तन की शर्तों के पालन की निगरानी की जायेगी एवं प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।	जी. हों।
27.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं गौतम मंत्रालय द्वारा समय समय पर वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के हित में जारी शर्तों का पालन किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं मौसम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के हित में जारी शर्तों का पालन किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।
28.	राज्य शासन एवं उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी एवं परियोजना पर लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।	कटनी-उमरिया-शहडोल-कोतमा (म.प्र./छत्तीसगढ़ बार्डर तक) रा.रा.क्र. 78 का भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की एनएचडीपी-4 परियोजना के अंतर्गत उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु उमरिया जिले के अंतर्गत प्रभावित 30.423 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन होने की अनुमति की शर्तों के अनुपालन में उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा परियोजना पर लागू समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। वचनपत्र संलग्न है।

Approved
परियोजना प्रबंधक

पैकेज-2 एवं 3, एन.एच.-78
म.प्र.सड़क विकास निगम लिमि.
संभाग शहडोल (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 33/अ-19(3)/2007-08



:: संशोधित आदेश ::

(दिनांक 14 जुलाई 2015 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख संचालक, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2738/एमपीआरडीसी / 2015-16 भोपाल दिनांक 25.05.2015 में उल्लेख किया है कि मेरास रुजतान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्दौर को 91.50 वृक्षारोपण हेतु 97.06 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33/अ-19(3)/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 द्वारा वन विभाग को अंतरित किया गया था तथा अंतर्गत शर्तों में यह स्पष्ट था कि प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन दो वर्ष के भीतर न होने की स्थिति में अंतरण स्वयं निरस्त समझा जावेगा। उक्त प्रोजेक्ट निर्धारित समयवधि में क्रियान्वित नहीं हो सका है। वन विभाग तत्समय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार भूमि को उपयुक्त पाया गया था :-

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	आगर	नालीखेड़ा	527	52.050
2	बड़ोद	रापही	818 / 1 / 1	28.730
3	बड़ोद	टोकड़ा	132 / 7	23.750
4		टोकड़ा	136	28.250
5		टोकड़ा	229	21.180
योग				151.780

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा संचालित रातना - चित्रकुट मार्ग (राजमार्ग क्र-11) हेतु 600 हेक्टेयर कटनी शहडोल-अनुपपुर-उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-76) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जबलपुर-मण्डला-चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12) हेतु 38.50 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 127.783 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। यदि उपरोक्तानुसार राजस्व भूमि वन विभाग को अंतरित की जाती है तो तीनों महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं का तत्परता से क्रियान्वयन संगत हो सकेगा। कृपया इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट कर। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल का पत्र क्रमांक 5408 दिनांक 10.07.2015 के माध्यम से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए निम्न क्रमानुसार राजस्व भूमि अंतरण का कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

1. कटनी शहडोल-अनुपपुर-उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-76) हेतु 52.683 हेक्टेयर

2. जबलपुर-मण्डला-चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12) हेतु 38.50 हेक्टेयर

Sten/Gen/let/ar.doc

(Signature)

चित्रकूट मार्ग (राजमार्ग क्र-11) हेतु 36.600 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के पत्र दिनांक 25.05.2015 एवं 10.07.2015 के आधार पर दिनांक 13.07.2015 को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि आवंटन आदेश जारी किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.) मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के द्वारा पत्र क्र 5673/ एमपीआरडीसी/2015-16 भोपाल दिनांक 14.07.2015 के माध्यम से अनुरोध किया है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2015 में संशोधन कर काली शाहडोल-अनुपपुर-उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जयलपुर-मण्डला-चित्तौरी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12) हेतु 38.50 हेक्टेयर राजस्व भूमि अन्तर्गत करने की कृपा करें।

3. कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33/3अ-19(3)/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 से निम्नानुसार भूमि वन विभाग को सशर्त आवंटित की गई थी :-

तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्र० एवं अभिलेख में अंकित उसकी मद	अभिलेख में अंकित भूमि का रकबा	वन विभाग को दी जाने हेतु प्रस्तावित की गई भूमि का रकबा
आगर	मालीखेडी	527 जो अभिलेख में निरस्ता चरगाई पर है। भूमि पडत भूमि प्रकार हेतु सुरक्षित अंकित है।	52.050 हेक्टेयर में से	20.00 हेक्टेयर
बडौद	रापडी	618/1 जो कि राजस्व अभिलेख में जमीन भूमि अंकित है।	29.730 हेक्टेयर में से	25.00 हेक्टेयर
बडौद	टोकड़ा	182 जो कि अभिलेख में चरगाई अंकित है।	23.570 हेक्टेयर में से	15.00 हेक्टेयर
		186 जो कि अभिलेख में निरस्ता चरोखर अंकित थी जिसे प्र.क्र 155/अ-59/2000-01 आदेश दिनांक 03.09.2001 द्वारा नष्ट भूमि केन धारित किया गया है।	26.250 हेक्टेयर में से	23.00 हेक्टेयर
		229 जो कि अभिलेख में गैरनुमकित चरगाई अंकित है।	21.180 हेक्टेयर में से	15.00 हेक्टेयर
योग				98.00 हेक्टेयर

उक्त आदेश में यह शर्त अंकित की गई थी कि किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है यह आदेश जारी होने के दो वर्ष अथवा किसी विशेष कारण से बढ़ाई अवधि के भीतर आरक्षित की गई

8/10/2015/Gen.letter.doc

शासन द्वारा शासक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह आदेश
मंजूर नहीं जावेगा तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग की अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा
वोपस/बयन (अ) प्रत्य में ली सकेगी।

4. वन मण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन को भेजे पत्र एवं कलेक्टर
जिला आगर मालवा को को पृष्ठ क्रमांक/मा.चि./14/2154 शाजापुर दिनांक 22.10.2014 में उल्लेख कि
गया है कि कलेक्टर शाजापुर के आदेश दिनांक 18.02.2008 के माध्यम से प्राप्त 98.00 हेक्टेयर गैर वन
भूमि हेतु आवेदक संस्था सुजलॉन, इन्फास्ट्रक्चर लि0 से कोई राशि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त नहीं हुई
है।

5. मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्दौर को पत्र क्रमांक/रीडर/15/146 आगर मालवा दिनांक
10.06.2015 जारी किया जाकर जवाब प्राप्त करने का कष्ट करें। मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड
इन्दौर द्वारा दिनांक 22.06.2015 को जवाब प्रस्तुत कर उसमें उल्लेख किया गया है कि मेसर्स
सुजलॉन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्दौर को 91.50 मगावाट का विण्ड फार्म प्रोजेक्ट बड़वानी जिले में
स्थापित किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1950 के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 97.06 हेक्टेयर
भूमि कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 33/अ-19(3)/2007-08 में पारित आदेश
दिनांक 18.02.2008 द्वारा वन विभाग को अन्तर्निहित की गई थी। उक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पक्ष में व
एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदाय की जा चुकी
थी किन्तु तत्पश्चात तत्समय संवैधानिक एवं शासकीय प्रावधान अनुसार उक्त वन भू-भाग पर वन
अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा उस भूमि पर कायज अनुसूचित
जनजाति निवासियों को प्रदाय कर दिया गया। अतः उक्त 97.06 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन
प्रस्ताव को अनुपयुक्त एवं निरस्त मानते हुए आवेदक संस्था ने उक्त भू-भाग अर्थात् वैकल्पिक
वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि के बदले कोई भी राशि भारत सरकार को जमा नहीं करवाई।

6. मेसर्स सुजलॉन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्दौर द्वारा वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई
उपरोक्त भूमि पर दो वर्ष से वृक्षारोपण नहीं किया जाने से कलेक्टर शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण
क्रमांक 33/अ-19(3)/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2008 को निरस्त किया जाता है।
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-25/36/2005/10-3 दिनांक 25.10.2005 एवं
परिपत्र क्रमांक एफ-25/36/2005/10-3 दिनांक 26 अक्टूबर 2005 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष
संचालक मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक
2738/एमपीआरडीसी/2015-16 भोपाल दिनांक 25.05.2015 पत्र क्रमांक 5403 दिनांक 10.0
2015 एवं पत्र क्र 5673/एमपीआरडीसी/2015-16 भोपाल दिनांक 14.07.2015 के अनुसार कट
शहडोल-अनुपपुर-उमरिया मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-78) हेतु 52.683 हेक्टेयर तथा जयलपुर-
मण्डला-चिल्पी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-12) हेतु 38.50 हेक्टेयर राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारो
पण हेतु जिला आगर मालवा की तहसील मण्डला की निम्नानुसार भूमि को मध्यप्रदेश गैर-राज
सहिता 1959 की धारा 237 के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर मध्यप्रदेश राजस्व

पुनर्निर्माण खण्ड-एक क्रमांक 7 के तहत नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वन विभाग को आवंटित की जाती है :-

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	रकबा हेक्टेयर में
1	बड़ौद	रापड़ा	818 / 1 / 1	28.730
2	बड़ौद	खोफड़ा	182 / 7	23.750
3		टोकड़ा	186	26.250
4		टोकड़ा	229	21.180 मेसे 12.453
योग				91.183

शर्तें :-

1. आवंटित की गई भूमि पूर्णतः शासन के स्वामित्व में रहेगी।
2. किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है या यह आदेश जारी होने के दो वर्ष अथवा किसी विशेष कारण से बड़ाई अवधि के भीतर आरक्षित की गई भूमि पर शासन निर्देशानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाता है या आरक्षित की गई भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में वर्णित प्रयोजन वैकल्पिक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग की अर्जित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने अधिकार में ली जा सकेगी।
3. आरक्षित भूमि पर से प्राथमिकताओं के अन्तर्गत निम्नलिखित उपयोग में किसी प्रकार की कोई रुकावट वन विभाग द्वारा उत्पन्न नहीं की जावेगी।
4. वन विभाग को जितनी भूमि प्रस्तावित परियोजना में दी जा रही है उतनी ही भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित रखी जाकर शेष भूमि राजस्व विभाग द्वारा वापस ली जा सकेगी।

तहसीलदार बड़ौद उनके तहसील क्षेत्राधीन अन्तर्गत आदेशानुसार अभिलेख में अमलदराने कर भूमि का कब्जा तत्काल वन विभाग शाजापुर को सौंपकर अमलशुदा खसरा नक्शा एवं कब्जा रसीद इस न्यायालय को भिजवायें।

(विनोद कुमार/शर्मा)

कलेक्टर

जिला-आगर मालवा ग0550

163-A

आगर मालवा, दिनांक जुलाई 2015

प्रति संचालक म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल ।

2. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल राज नुं

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमर-राजस्व :

4. तहसीलदार, तहसील आगर, बडौद को रोड भेज कर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल करायें तथा स्थल पर हस्ताक्षर अभि चिन्हित कर विभागीय अधिकारी को अधिपत्र दिलाये जाने हेतु पालनार्थ ।

5. सुजलोन गुजरात विन्ड पार्क लिमिटेड द्वारा विहार ए0 बी0 रोड इन्दौर कर ओर सूचनार्थ

कलेक्टर 14/7/2015

जिला-आगर मालवा म0प्र0

हम पंचान यह पंचनामा लिखा देने वाले साथ साथ कर देते हैं कि आज दिनांक 16/02/2016 को स्थान ग्राम पंचायत डोकड़ा के ग्राम डोकड़ा में वन परिसर में अधि. के पत्र क्र. 115/16/02/2016 व वन मं. शां. शांजापुर के पत्र क्र. /मौ.पंच./ 2016/379/दि. 15.2.16 के आदेश पर पटवारी ग्राम डोकड़ा श्री गोवर्धन सिंह केलकर पं. ह. नं. 20 व परि. सहा. आगर श्री अशोक देवड़ा MP RD द्वारा अधि. इन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी के साथ वन कर्मि भूमि हस्तान्तरण के सर्वे हेतु उपस्थित हुए, मौके पर पटवारी द्वारा बताया गई भूमि सर्वे क्र. 229 का GP S द्वारा परिया कैलकुलेशन किया गया, भूमि के चारों कोनों की GP S रीडिंग ली गई, जिसका परिया कैलकुलेशन रकबा 15.66 पाया गया, सर्वे की गई भूमि अतिरिक्त से मुक्त है व मिट्टी लाल, मुरभी दोमट प्रकार की है, सर्वे की गई भूमि में पलाश, चीलाफल व करोंदा प्रजाति की झाड़ियाँ हैं। GP S रीडिंग निम्नानुसार है:

① उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ लेकर दक्षिण की ओर:

N 23° 49' 30.0"
E 075° 51' 56.1"

③ N 23° 49' 21.0"
E 075° 52' 07.7"

② N 23° 49' 29.8"
E 075° 51' 56.1"

④ N 23° 49' 32.2"
E 075° 52' 04.4"

⑤ राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 24 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
अतिरिक्त बाईलान्थ विद्युत लाइन 300 मीटर दूरी पर स्थित है।
13.188 हे. वन भूमि है।

सर्वे उपरान्त मौके पर मौका पंचनामा तैयार किया गया पद कर सुनकर उपस्थित पंचों ने पूर्ण दृष्टि से हवाला के हस्ताक्षर किये जो पत्र पड़े काम आये।

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया

(Signature)

मि. म. अष्टनाथदास शांजापुर
मि. जोशी अतिरिक्त डोकड़ा

16.02.2016
अ. ब. ल.

16/2/16
मौका पंचनामा
अतिरिक्त डोकड़ा

16/2/16
पंच. आगरा

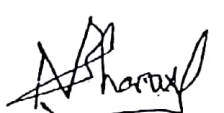
पंचनामा
मि. अशोक देवड़ा
मि. जोशी अतिरिक्त

अतिरिक्त
मौका पंचनामा

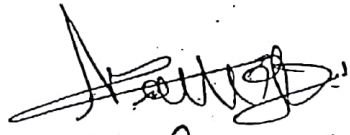
मैं नरेन्द्र अखण्ड उपवन क्षेत्रपाल वडोद स्व शकेश कुम्भकार
वनरक्षक वीर वडोद हस्ताक्षर कर यह लिख देते हैं कि आज
दिनांक 16/02/16 को ग्राम टोकड़ा की वन विभाग की आवधिक
भूमि सर्वे क्र. 229 रकबा 15 हे. में से 12.453 हे. भूमि का
पटवारी ग्राम द्वारा मौजे पर सीमांकन कर सीमाचिन्ह
स्थापित करवा दिये गये, हमारे द्वारा मौजे पर सीमाएं समझ
ली गई हैं। मौजे पर उपरोक्त भूमि का सीमांकन अनुसार कव्वा
स्थापित कर लिया गया है।


Rakesh Kumar
P. S. B. S. D.
अ. व. व. 11/02/16

महाराष्ट्र


नरेन्द्र अखण्ड
प. स. व. स. ड.

① गोविन्द सिंह
गोविन्द सिंह अ. व. व. 11/02/16
अ. व. व. 11/02/16


पटवारी ह. नं. 20
16/02/16

② अ. व. व. 11/02/16
अ. व. व. 11/02/16
अ. व. व. 11/02/16

ग्राम के व्योरा हैस्टोर में एंव करो का व्योरा रुपये पैसों में

खसरा

125126748692

हल्का इकतेराबडौर

रा. नि. नं बीजानगरी

तहसील बड़ीद.

जिला आगर मालवा

वर्ष २०१६-२०१७.

क्र.सं.	खेतावर (आर यू.ए. भूमि खाल में लक्षित न हो तो उसका वर्णन)	कच्चेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौलूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या भाग का क्षेत्रफल	खाले की भूमि						खाले के बाहर के क्षेत्रों में बाई गई फसल का नाम	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई	पड़ती का क्षेत्रफल	वातु वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अथवा ५ वर्ष से अधिक	११		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२२९	शासकीय										

६८१

श्रीमान कलेक्टर
महोदय गानगापुर के
प्र क्र ३३/ अ
-१९९(३)
/२००७-०८ आदि
१८-२/२००८ के
अनुसार
श्रीमान तहसीलदार
महोदय के प्र क्र १
-२/०८/७९४-९५
आदि १२/३/२००८
के पालन में सर्वे क्र
२२१ रकबा ६.१८
को तहसीलदार
दरमई एव १५.००
है ० वन विभाग का
प्रमाणित है
अमल किया गया
न्यायालय कलेक्टर
महोदय
जिला आगरा
मालवा के प्र क्र
३३/ अ-१९(३)
/२००७-०८
संशोधित आदेश

LC 1/106

१

श्रीमान कलेक्टर महोदय गान्धार के प्र क्र ३३/ अ -१९(३) १२००७-०८ आदि १८-२/२००८ के अनुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय के प्र क्र १०/८/९९४-९५ आदि १२/३/२००८ के पालन में सर्व क्र २२९ रकबा ६.१८ को नै. मुनिन एरनई एवं १५.०० ६० वन विभाग का वसंतीना हेतु अन्त किया गया मायालय करवेटर महोदय जिला आगर मालवा के प्र क्र ३३/ अ-१९(३) १२००७-०८ संशोधित आदेश

हस्ताक्षर करो का ब्योरा रुपये पेसों में

खसरा

11/11/2019 10:08:10 ११:१४

NIC-VER4-barod1



125126748692

हल्का इकलराबडौद

रा. नि. नं बीजानगरी

तहसील बड़ौद.

जिला अगर मालवा

वर्ष २०१६-२०१७.

खेत (और भूमि खेत) का नाम	कच्चा/रकबा का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देश राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे का रकम और उस पट्टे पर दिये गए भाग का क्षेत्रफल	खेत की भूमि					खेत के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल		कैफियत
			क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई	पड़ती का क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम	क्षेत्रफल	
३	१	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
										दिनांक १४-०७-२०१५ से सर्वे न २२९ रकबा ३१.१८ हे० में से १२.४५ हे० इन विभाग को ब्रह्मरोषण हेतु सुरक्षित रखी है

प्रतिनिधि देने वाले के हस्ताक्षर:
नाम, पद एवं दिनांक:

FC
११/११/२०१९

मै गरीब अखण्ड उपवन क्षेत्रपाल वडोद एवं रमेश कुमार
वनरक्षक लीट वडोद हस्ताक्षर कर यह लिख देते हैं कि
आज दिनांक 29/09/2016 को ग्राम रापटो की वन विभाग
की आवंटित भूमि सर्वे क्र. 818/1/1 रकबा 28.730 है.
भूमि का पटवारी ग्राम द्वारा मौजे पर सीमांकन कर
हमारे द्वारा मौजे पर सीमाएं समझ ली गई हैं मौजे पर
उपरोक्त भूमि का कल्ला जाफ़ कर लिया गया

जवाब

समझ

29/9/16

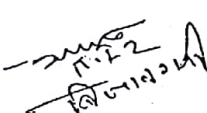
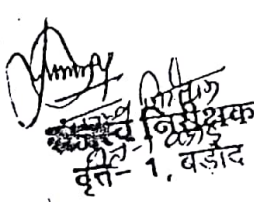
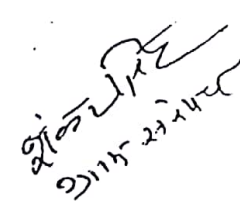
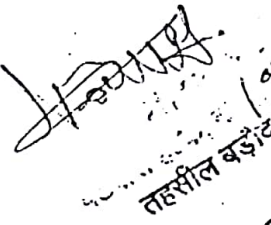
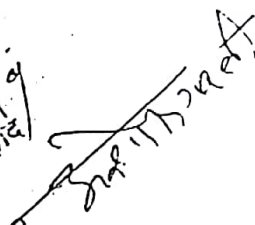
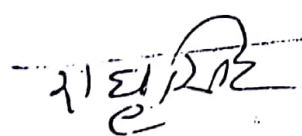
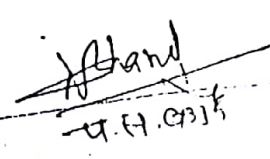
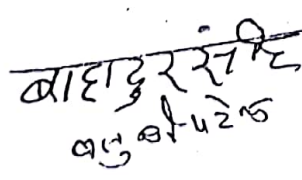
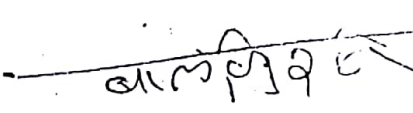
बाहादुर सिंह

गोरधन सिंह केलकर
पटवारी हस्ता. नं. 20..
तहसील वडोद

राधु सिंह

Rakesh Kumar
A.G. Bared
29/09/16

हम पंचायत गांव गांधी तहसील ब्लॉक के लेजर यह पंचनामा तैयार करते हैं कि आप दिनांक 29/11/16 को संयुक्त वीमांकन दल मेले पर आये व श्री माज तहसीलदार ग्रेडिंग ब्लॉक के पत्र संक्र/री-1/9016-17 दिनांक 29/11/16 के पालन में वन गण्डल आगर को हटाकर नई अग्नि लैव आंक 818 कि-1 बरखा 28/73 का वन गण्डल (ईलाधिकारी) श्री नरेन्द्र जी शायद डीपी रेजर की उपस्थिति में वीमांकन किया। अग्नि लैव नंबर 818 कि-1 बरखा 28/73 लेजर की चर्चुषीया कागज की गई व पात्र के निष्कर्ष कागज छिमे गये। मेले पर उपस्थित विभाग की ओर से उपस्थित श्री नरेन्द्र जी शायद डीपी रेजर द्वारा उक्त अग्नि की चर्चुषीया समझी गई। चर्चुषीया समझाकर पंचनामा लिखा जाकर पदा पुनः गथा बाद हस्ताक्षर करवाये।

को ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II
खसरा

तिथि : १०/०४/२०१६ ११:०५

NIC-VER4-baroda

148239001



220

हल्का बिनायाग बड़ौद रा. नि. नं बीजानगारी

तहसील बड़ौद.

जिला आगर मालवा

वर्ष २०१६-२०१७.

खेतों का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिग्रहण जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौलामी कायतकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या भाग का क्षेत्रफल	खेत की भूमि					खेत के बाहर के क्षेत्रों में बोंई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल		कैलकत
		क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई पड़ती का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अथवा ५ वर्ष से अधिक	क्षेत्रफल	
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
रासकौय									न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला आगर मालवा के प्र क्र ३३/ अ-१६(३) १२००७-०८ संशोधित आदेशा दिनांक १४-०७-२०१५ में नंबर = ५१८/११ रकबा २८.०३ है० वन विभाग को वेश्यायन हेतु सुरक्षित रखा है

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम पर पद एवं स्थिति :

RC

11/11/16